नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टाक निम्नानुसार था:—

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

	1.7.95 की स्थिति के अनुसार (अनन्तिम)	1.10.95 की स्थिति के अनुसार	1.11.95 की स्थिति के अनुसार (अनंतिम)
गेहूं	19.17	16.78	15.77
चावल	16.44	13.00	12.41
जोड़	35.61	29.78	28.18

(ग) और (घ) बफर स्टाक रखने संबंधी वर्तमान नीति के अनुसार उपर्युक्त स्टाक सरकार द्वारा रखे जाने वाले न्यूनतम बफर मानदण्डों से कहीं अधिक है। जिसका ब्योरा निम्नानुसार है:—

(आंकड़े मिलियन मीटरी टन में)

तारीख	गेहूं	चावल	जोड़
पहली अप्रैल	3.7	10.8	14.5
पहली जुलाई	13.1	9.2	22.3
पहली अक्तूबर	10.6	6.0	16.6
पहली जनवरी	7.7	7.7	15.4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने में उपयोग करने के अलावा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिशेष स्टाक का जवाहर रोजगार योजना, पोषाहार कार्यक्रम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के होस्टलों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा चलाई जा रही खाद्य विधायन यूनिटों, मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और इसकी फ्रेन्चाइज्ड यूनिटों तथा मिड-डे-मील स्कीम जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन उपयोग किया जाए। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम घरेलू खपत और निर्यात के प्रयोजन के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री कर रहा है। खाद्यान्नों की चालू वसूली के लिए भण्डारण स्थान खाली करने और खाद्यान्नों के बफर स्टाक पर रख-रखाव लागत के प्रति खर्च को कम करने की आवश्यकता अधिशेष स्टाक में कमी लाने के मुख्य कारण हैं।

Proposal for auction Platforms for Bidi Tobacco in Andhra Pradesh

1399. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up auction platforms for tobacco in Andhra Pradesh by the Tobacco Board;

(b) if so, the proposed, location of such platforms; and

(c) whether this proposal would benefit a large number of farmers in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir. There is no proposal to set up new auction platforms for tobacco in Andhra Pradesh. However, during 1994-95, 19 auction platforms were operated in Andhra Pradesh by the Tobacco Board.

(b) and (c) Does not arise.

Request of Additional Quota of Wheat etc.

1400. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether request have been received from the State Governments for enhancement of their quota of wheat, rice, sugar etc.;

(b) if so, the details thereof;

(c) the action taken thereon; and

(d) the manner in which the demands of the States are to be met in 1996?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) During 1995, requests have been received from the State Governments/UT Administrations of Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra,

Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tamilnadu, Tripura, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu for additional allocation/enhancement of their monthly wheat quotas. Similarly, requests have been received during 1995 from Andhra Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tamilnadu and Daman & Diu for additional allocation/enhancement of their rice quotas. A statement showing the additional allocations of rice and wheat made to various States/Union Territories during 1995 is attached (Annexure). [*See* Appendix 175, Annexure No. 40]

Levy sugar allocations for Public Distribution System are not made on the basis of the demands received from the States/Union Territories and are made generally on uniform norm of 425 gms. per capita monthly availability to the projected population as on 1.10.86, effective from 1.2.1987. Keeping in view the improved availability of sugar during the season 1994-95, an ad-hoc increase of 5% in the monthly allocation of levy sugar has been restored with effect from September, 1995.

(d) There are adequate stocks of wheat and rice in the Central Pool and no difficulty is foreseen at present to meet the requirements of the public Distribution System during 1996. In view of better availability of sugar, the Government has decided to allocate levy sugar as per 1991 census effective from 1.1.1996.

Assessment of Infrastructure for Mineral Exports

1401. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be please to state:

(a) whether any assessment with regard to the adequacy or otherwise of the infrastructure available in the country for the growth of mineral exports has been made by Government;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) the manner in which Government propose to remove the deficiencies in the infrastructure to promote mineral exports?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Lack of adequate infrastructural facilities have constrained the growth in exports including the exports of minerals. No specific study has been conducted by this Ministry to determine the adequacy of available infrastructure for the growth of mineral exports.

(c) To ease infrastructural constraints, Government is constantly interacting with the State Governments, Railways and Port Authorities.

देश में रोजगार के अवसर

1402. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चालू योजनावधि के दौरान 30 जून, 1995 तक अनुमानतः कितने रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ग) इस योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1995 तक श्रमिकों की संख्या में कितने अतिरिक्त श्रमिकों की वृद्धि हुई;

(घ) क्या सरकार कुछ नये रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है; और

(ङ) रोजगार में लगे विशेषकर असंगठित क्षेत्रों और ग्रामीण श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है, जिन्हें कि आंशिक रोजगार मिला हुआ है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) (क) देश में चालू योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1995 तक सृजित रोजगार अवसरों की अनुमानित संख्या 18.78 मिलियन है। 30 जून, 1995 तक सृजित रोजगार अवसरों का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) मुक्त रोजगार की पिछली बाकी कमी का अनुमान आठवीं योजना के शुरू में 17 मिलियन का लगाया गया था।

(ग) 1992—95 के दौरान श्रम शक्ति में 20.47